भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1790
दिनांक 05 दिसंबर, 2024

पेट्रोलियम उत्पादों के आयात में कमी

†1790. श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार आयात को कम करने के लिए पेट्रोलियम और गैस क्षेत्र को विकसित करने हेतु कोई दीर्घकालिक योजना बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के कार्यान्वयन से आयात में कितनी कमी आने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा आयात को कम करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (घ) : सरकार ने कच्चे तेल पर निर्भरता को कम करने के लिए एक बहु आयामी कार्यनीति अपनाई हैं जिसमें अन्य बातो के साथ साथ अर्थव्यवस्था मे प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को बढाने और गैस आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में देशभर में ईंधन / फीडस्टोक के रूप मे प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढावा देकर मांग प्रतिस्थापन, एथेनॉल और दूसरी पीढ़ी के एथेनॉल, संपीड़ित जैव गैस एवम बायोडीजल जैसे नवीकरणीय तथा वैकल्पिक ईंधन को बढावा देना,इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग आधारभूत संरचना का निर्माण करना,रिफाइनरी प्रोसेस सुधार करना,ऊर्जा दक्षता और संरक्षण को बढावा देना, विभिन्न नीतिगत पहलो के माध्यम से तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन को बढाने के प्रयास आदि शामिल हैं। ऑटोमोटिव ईंधन के रूप मे संपीड़ित जैव गैस (सीबीजी) के उपयोग को बढावा देने के लिए, किफायती परिवहन के लिए दीर्घकालिक विकल्प (सतत)पहल की भी शुरुआत की गई। एथेलोन मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम जैसे अन्य वैकल्पिक ईंधनों पर सरकार के बल देने के परिणाम स्वरूप ईएसवाई 2013 - 2014 से ईएसवाई 2023 – 2024 तक लगभग 1.09 लाख करोड रुपये की विदेशी विनिमय की बचत हुई हैं।

हालांकि विगत कुछ वर्षों में औद्योगीकरण, शहरीकरण, परिवहन आवश्यकताओं, बुनियादी ढांचे का विकास, बढ़ती आय,जीवन स्तर में सुधार, आधुनिक ऊर्जा तक बढ़ती पहुंच के साथ साथ निजी खपत और सकल स्थिर पूंजी निर्माण में वृद्धि आदि के कारण दीर्घकालिक आर्थिक विकास के कारण भारत की ऊर्जा खपत लगातार बढ़ रही हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कच्चे तेल का आयात बढ़ रहा हैं।

सरकार घरेलू तेल एवम गैस उत्पादन को बढावा देने के लिए विभिन्न कदम उठा रही हैं, जिसमें अन्य बातो के साथ साथ निम्नलिखित भी शामिल हैं :

i. हाइड्रोकार्बन खोजों के शीघ्र मुद्रीकरण के लिए पीएससी व्यवस्था के तहत नीति, 2014
ii. खोजे गए छोटे क्षेत्र नीति, 2015
iii. हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (एचईएलपी), 2016
iv. पीएससी के विस्तार के लिए नीति, 2016 और 2017
v. कोल बेड मीथेन के शीघ्र मुद्रीकरण के लिए नीति, 2017
vi. राष्ट्रीय डेटा रिपोजिटरी की स्थापना, 2017
vii. राष्ट्रीय भूकंपीय कार्यक्रम, 2017 के तहत तलछटी बेसिन में गैर-मूल्यांकित क्षेत्रों का मूल्यांकन।
viii. पूर्व-नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (प्री-एनईएलपी), 2016 और 2017 के तहत खोजे गए क्षेत्रों और अन्वेषण ब्लॉकों के लिए पीएससी के विस्तार के लिए नीति ढांचा।
ix. तेल और गैस के लिए उन्नत रिकवरी विधियों को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने की नीति, 2018
x. मौजूदा उत्पादन साझाकरण संविदाओं (पीएससी), कोल बेड मीथेन (सीबीएम) संविदाओं और नामांकन क्षेत्रों, 2018 के तहत अपरंपरागत हाइड्रोकार्बन की खोज और दोहन के लिए नीति ढांचा।
xi. प्राकृतिक गैस विपणन सुधार, 2020
xii. बोलीदाताओं को आकर्षित करने के लिए श्रेणी II और III बेसिनों के तहत ओएएलपी ब्लॉकों में चरण-I में कम रॉयल्टी दरें, शून्य राजस्व हिस्सेदारी (अप्रत्याशित लाभ तक) और कोई ड्रिलिंग प्रतिबद्धता नहीं।
xiii. अपतटीय क्षेत्र में लगभग 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर (एसकेएम) 'नो-गो' क्षेत्र को छोड़ना, जो दशकों से अन्वेषण के लिए अवरुद्ध था।
xiv. सरकार भूमि और अपतटीय क्षेत्रों में भूकंपीय डेटा के अधिग्रहण और स्ट्रेटीग्राफिक कूपों की ड्रिलिंग के लिए लगभग 7500 करोड़ रुपये खर्च भी कर रही है, ताकि बोलीदाताओं को भारतीय तलछटी बेसिनों का गुणवत्तापूर्ण डेटा उपलब्ध कराया जा सके। सरकार ने भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) से परे ऑनलैण्ड पर 20,000 एलकेएम और अपतटीय क्षेत्र में 30,000 एलकेएम के अतिरिक्त 2डी भूकंपीय डेटा के अधिग्रहण को मंजूरी दी है।

****